

78

सं० 1189 / IV(2)-श०वि०-11-28(एन०यू०आर०एम०)/०८

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 13 सितम्बर, 2011

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के 12 चौराहों के सुधार हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा०स०-67/IV-श०वि०-09-28 (एन०यू०आर०एम०)/०८ दिनांक 20-3-2009 एवं शासनादेश संख्या 170/IV(2)-श०वि०-11-28(एन०यू०आर०एम०)/०८ दिनांक 4-2-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के चौराहों के सुधार की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी०पी०आर० ₹ 2005.00 लाख के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित कुल ₹ 501.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार की केन्द्रीय संस्तुति एवं मॉनिटरिंग कमेटी की दिनांक 21-6-2011 को हुई 97वीं बैठक में हरिद्वार के 12 चौराहों के सुधार की पुनरीक्षित डी०पी०आर० ₹ 1765.05 लाख (₹ सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पांच हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें कुल केन्द्रांश ₹ 1712.04 लाख तथा कुल राज्यांश ₹ 353.01 लाख होता है।

3- उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PFI/2011-444 दिनांक 27-7-2011 द्वारा उपरोक्त परियोजना हेतु द्वितीय किस्त ₹ 163.82 लाख की अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश ₹ 163.82 लाख तथा इसके सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 40.96 लाख सहित कुल धनराशि ₹ 204.78 लाख (₹ दो करोड़ चार लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु

आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹ 204.78 लाख (₹ दो करोड़ चार लाख अट्ठत्तर हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त धनराशि को अपने पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी और इसका आवश्यकता के अनुसार ही पी0एल0ए0 से आहरण किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या भा0स0-67/IV-श0वि0-09-28(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 20-3-2009 एवं शासनादेश संख्या 170/IV(2)-श0वि0-11-28(एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 4-2-2011 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित कार्यों पर ही किया जायेगा।
5. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियन्ता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत कार्य कराने समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
10. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2011-12 के आय-व्यय के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०-03/XXVII(2)/2011, दिनांक 09 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

1189
सं०

(1)/IV(2)-श०वि०-11, तददिनांक। 13-9-11

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी।
6. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
12. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
13. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।